1000 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में आवेदन किया है। यह राशि 25 फरवरी को सरकार के खजाने में पहुंच जाएगी। इस वित्त वर्ष में अब सरकार किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं ले सकेगी।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार 22 फरवरी 2020

न्यूज गैलरी

गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई जीओएम की बैठक

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक हुई। माना जा रहा है कि शुक्रवार की बैठक में जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन के बारे में चर्चा की गई। इस बैठक में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल शामिल हुईं।जीओएम में जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि यह अभी पता नहीं चल पाया है कि सरकार अधिनियम में क्या संशोधन करने जा रही है। (प्रेट्र)

लोगों पर समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जानी चाहिए : कांग्रेस

नई दिल्ली : कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि लोगों पर एक समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जानी चाहिए। बल्कि यह वैकल्पिक होनी चाहिए। यहां 'छात्र संसद' के 10वें संस्करण में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि समान नागरिक संहिता को स्वैच्छिक बनाना बहुत बढ़िया कदम होगा। सुरजेवाला ने कहा, 'समान नागरिक संहिता का अहम तथ्य यह है कि इसे जबरन आप पर थोपा नहीं जा सकता है, यह वैकल्पिक होनी चाहिए, अनिवार्य नहीं। यह स्वैच्छिक होनी चाहिए और यह बड़ा कदम होगा।' पिछले साल भाजपा का चुनावी घोषणापत्र जारी करते हुए उसके वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा था कि उनकी पार्टी देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। देश में जाति आधारित हिंसा के बारे में पूछे जाने पर सुरजेवाला ने कहा कि किसी को भी सच स्वीकार करने में शर्म नहीं करना चाहिए। (प्रेट्र)

कमलनाथ ने फिर उठाए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल

छिंदवाड़ा : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने लगातार दूसरे दिन सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए।

शुक्रवार को यहां मीडिया से चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो इसके सबूत क्यों नहीं हैं? मीडिया से ही देशवासियों को पता चला कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन अब तक सुबूत सामने नहीं आए हैं। गुरुवार को भी कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में कहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 90 हजार पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया था। इसे लेकर कोई नहीं बोलता। यह कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की। कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक की? कैसे की? देश को कुछ तो बताइए। (नईदुनिया)

एससी-बीसी क्रीमीलेयर की 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंद

झटका ▶ खराब वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए पंजाब सरकार का फैसला

अगला नंबर हो सकता है बड़े व मध्यम किसानों का

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

पंजाब की खराब वित्तीय हालत को सुधारने के लिए प्रदेश सरकार तरह-तरह के उपाय कर रही है। उसने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर को दी जाती 200 यूनिट मुफ्त बिजली बंद कर दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या अगला नंबर बड़े और मध्यम किसानों का है। दस एकड़ से ज्यादा मध्यम और बड़े किसानों को अगर सब्सिडी से बाहर कर दिया जाता है तो सरकार 3907 करोड़ रुपये बचा सकती है।

काबिले गौर है कि बीते दो दिसंबर को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वित्त विभाग के साथ बैठक की थी, जिसमें वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाने के लिए सब्सिडियों को तर्कसंगत बनाने का फैसला हुआ था। साथ ही अन्य विभागों के खर्चों को भी कम करने की योजना तैयार की गई। अनुसूचित जाति, पिछड़े और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) वालों को 200 यूनिट बिजली निःशुल्क देने के मामले में यह तथ्य सामने आया कि इसमें से क्रीमी लेयर को बाहर किया जाए और एक किलोवाट तक के लोड वाले केवल गरीब लोगों को यह सुविधा प्रदान की जाए। मध्यम और बड़े किसानों को दी जाने वाली बिजली सब्सिडी भी बंद करने का सुझाव दिया गया था। इस समय किसानों, एससी और उद्योगों को कुल 9,674 करोड़ की बिजली सब्सिडी दी जा रही है। इसमें किसानों को 6,060 करोड़, एससी, बीसी समुदाय को 200 यूनिट फ्री देने में 1623 करोड़ और इंडस्ट्री को 1990 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा तीन हजार करोड़ का पिछला बकाया भी है। यानी चालू वित्त वर्ष में सरकार को 12397.71 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी है।

देना होगा शपथपत्र: जिन लोगों को यह सुविधा चाहिए उन्हें एक शपथपत्र देकर बताना होगा कि वह एससी, बीसी, बीपीएल कैटेगरी के हैं और उनका मंजूरशुदा लोड एक किलोवाट से कम है। वे आयकर के घेरे में नहीं आते।

इन वर्गों को नहीं मिलेगी सुविधा

पावरकॉम ने गुरुवार को नोटिफिकेशन जारी कर साफ किया कि निम्न वर्गों को यह सुविधा नहीं मिलेगी-

- संवैधानिक पदों पर बैठे पूर्व और वर्तमान अधिकारी व नेता
- पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्यमंत्री, सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के चेयरमैन आदि
- राज्य सरकार व केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स
- ऐसे सेवानिवृत्त लोग जिनकी पेंशन दस हजार रुपये से कम है
- प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट आदि।

नीतीश बोले डीजीपी से, शराबबंदी पर भाषण अच्छा था, अब काम भी वैसा कराएं

जासं, पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे का शराबबंदी पर भाषण बहुत पसंद आया, लेकिन उन्होंने यह नसीहत भी दे डाली कि जो भाषण दिया, उसे क्रियान्वित भी कराएं। इसी से बिहार और यहां की पुलिस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में शुक्रवार को आयोजित 'एक शाम शहीदों के नाम' कार्यक्रम में डीजीपी ने शराबबंदी को राज्य सरकार का ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा था कि शराब का धंधा करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। नीतीश ने कहा कि इसे क्रियान्वित कराइए, तभी बिहार की प्रतिष्ठा और पुलिस बल के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ेगा। पुलिस वालों ने शराब नहीं पीने और न पीने देने का संकल्प तो बहुत पहले ही ले लिया है। जरूरत संकल्प को पूरा करने की है। होम डिलीवरी वाली बात वही करते हैं, जो पीने के चक्कर में रहते हैं :

मुख्यमंत्री ने शराब की होम डिलीवरी जैसे बयान देने वाले विपक्ष के नेताओं पर भी तंज कसते हुए कहा कि ऐसा वही लोग कहते हैं जो पीने के चक्कर में रहते हैं। सीएम ने कहा कि शराबबंदी के समय लोग कहते थे कि पर्यटकों की संख्या घटेगी। हमने कहा था कि यहां पर्यटक पीने नहीं आते हैं। यह सही साबित हुआ। आज बिहार में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। 3.50 करोड़ से ज्यादा पर्यटक राज्य में आए हैं।

मप्र में स्कूली छात्रों के वजीफे बंद कर सकती है सरकार

मनोज तिवारी, भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार पहली से आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा के विद्यार्थियों का वजीफा (छात्रवृत्ति) बंद कर सकती है। इससे सरकार को सालाना 200 करोड़ रुपये की बचत होगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा, आदिमजाति कल्याण और पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अफसरों में इस पर सहमति बन गई है। प्रस्ताव से वित्त विभाग भी सहमत है। अब प्रस्ताव तीनों विभागों के मंत्रियों और फिर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद आठ कक्षाओं तक करीब 15 लाख विद्यार्थियों का वजीफा बंद हो जाएगा। इस निर्णय को सरकार की आर्थिक तंगी से जोड़कर देखा जा रहा है।

सरकार पिछले सवा साल से अनुपयोगी योजनाओं को बंद और एक जैसे लाभ वाली योजनाओं का पुनर्गठन करा रही है। इसी कड़ी में तीनों विभागों के अफसरों की पिछले माह हुई बैठक में वजीफा बंद करने पर सहमति बनी है। हालांकि वजीफा बंद करने से बचने वाले 200 करोड़ रुपये दूसरे विभाग को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि यह राशि स्कूलों की अधोसंरचना विकास के लिए संबंधित विभागों को बजट में दी जाएगी और विभाग इससे बिजली, टाटपट्टी, पानी, फर्नीचर के काम कर सकेंगे। वर्तमान में इन विद्यार्थियों को 20, 25 एवं 60 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जा रही है। उन्हें साल में 10 माह छात्रवृत्ति दी जाती है। ज्ञात हो कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पहली से आठवीं तक 75 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं।

तैयारी

- स्कूल शिक्षा, आदिमजाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग ने तैयार किया संयुक्त प्रस्ताव
- मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद करीब 15 लाख छात्र होंगे प्रभावित

सब कुछ फ्री तो क्यों दें वजीफा: वजीफा बंद करने को लेकर अधिकारियों का तर्क है कि 'निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई)' आने के बाद से पहली से आठवीं के विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है। उन्हें स्कूल ड्रेस, स्कूल आने-जाने के लिए साइकिल और किताबें मुफ्त दी जा रही हैं। जब पढ़ाई पर विद्यार्थियों का पैसा खर्च ही नहीं हो रहा है, तो वजीफा क्यों दें। अधिकारियों का कहना है कि वैसे भी वजीफे की राशि इतनी कम है कि उससे विद्यार्थी को कोई फायदा नहीं है। ऐसे में योजना बंद या वजीफे की राशि बढ़ानी पड़ेगी।

पूर्व विधायक चाह रहे कैशलेस मेडिकल यात्रा भत्ता और हाउसिंग सोसायटी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

- हरियाणा के पूर्व विधायकों की सीएम, हुड्डा, स्पीकर व चौटाला के यहां दस्तक
- अधिकारियों को मिल रही सुविधाओं का दिया हवाला, कहा नहीं चाहिए बढ़ी पेंशन

हरियाणा के पूर्व विधायकों ने सांसदों व पूर्व सांसदों की तर्ज पर विधायकों व पूर्व विधायकों को भी कैशलेस मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग कर दी है। पूर्व विधायक हरियाणा सरकार के रेस्ट हाउस में कमरे नहीं मिलने से खासे आहत हैं। रिटायर्ड अधिकारियों से जहां 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमरे का रेट वसूला जाता है, वहीं पूर्व विधायकों को यदि कमरा मिल जाए तो उनसे 500 रुपये वसूल किए जा रहे हैं।

हरियाणा की पूर्व विधायक एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। राज्य में करीब 300 पूर्व विधायक हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष नफे सिंह राठी, महासचिव रामबीर सिंह पटौदी, पूरण सिंह डाबड़ा और रण सिंह मान के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सदस्य पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता अभय सिंह चौटाला से भी मिले।

पूर्व विधायकों ने मुख्यमंत्री को साफ कह दिया कि वे अपनी पेंशन में बढ़ोतरी के लिए नहीं आए हैं, लेकिन सांसदों व पूर्व सांसदों की तर्ज पर विधायकों व पूर्व विधायकों को कैशलेस मेडिकल सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की जा रही है। नफे सिंह राठी ने कहा कि हरियाणा निवास दिल्ली व एमएलए हास्टल चंडीगढ़ में पूर्व विधायकों को कमरे नहीं मिलते। इन पर अधिकारियों व उनके रिश्तेदारों का कब्जा रहता है।

नफे सिंह राठी के अनुसार मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जिस तरह से अधिकारियों की ग्रुप हाउसिंग सोसायटी बनाई गई है, उसी तरह से इस सोसायटी के ठीक सामने हरियाणा सरकार की जमीन खाली पड़ी है। इस जमीन का जो भी रेट है, उस पर पूर्व विधायकों को यह जमीन ग्रुप हाउसिंग के लिए अलॉट की जानी चाहिए, ताकि वह यहां रह सकें।

प्रधानमंत्री मोदी ने ख्वाजा की दरगाह के लिए भेजी चादर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 808वें उर्स पर दरगाह में चादरपोशी के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल को चादर सौंपी। मोदी की ओर से छठी बार अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादरपोशी की जाएगी। एएनआइ

'सौभाग्य' में फिर घोटाला, पांच लाख घरों तक नहीं पहुंची बिजली

नईदुनिया, भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर-घर बिजली पहुंचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' मध्य प्रदेश में न सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, बल्कि सौ फीसद मीटरिंग का दावा करने के बाद भी पांच लाख से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां बिजली पहुंची ही नहीं। राज्य सरकार ने इसकी छानबीन की तो छह महीनों की कवायद के बाद ये जानकारी एकत्र हो पाई कि सौ फीसद मीटरिंग के दावे के बाद भी योजना का मकसद पूरा नहीं हो पाया है। पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होने के बाद अब सिर्फ पूर्व क्षेत्र बिजली कंपनी ने 569 करोड़ रुपये की मांग और की है। तीनों कंपनी का खर्च लगभग 15 सौ करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

चौंकाने वाली बात ये है कि पिछली सरकार ने प्रदेश में सौ फीसद गांव तक बिजली पहुंचाने का दावा किया था। गौरतलब है कि सौभाग्य योजना में कई तरह की गड़बड़ियां पहले सामने आ चुकी हैं। डिंडौरी-मंडला में 10 करोड़ रुपये की वसूली के साथ नौ इंजीनियरों को निलंबित किया गया है।

राष्ट्रवाद शब्द समाज के लिए ठीक नहीं : भागवत

जागरण संवाददाता, रांची

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रवाद शब्द समाज के लिए ठीक नहीं है। यह शब्द सीमित करता है। वहीं, राष्ट्रीयता शब्द विस्तार देता है। वाद शब्द हमेशा स्वार्थ के लिए होता है। स्वार्थ की पूर्ति होते ही मोह भंग हो सकता है, जबकि राष्ट्रीयता से आत्मिक जुड़ाव होता है। रांची में अपने पांच दिवसीय दौरे पर पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत के दूसरे दिन आइआइएम सभागार में राज्य के प्रमुख लोगों से संवाद कर रहे थे।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में उपस्थित एक सज्जन ने राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता को लेकर संघ का विचार जानना चाहा। इस पर उन्होंने कहा कि राष्ट्र किसी वाद से नहीं बंधा है। राष्ट्र जैविक शब्द है जबकि राष्ट्रवाद कृत्रिम शब्द है। राष्ट्र में जीवन होता है, वह बीमार पड़ता है, फिर स्वस्थ होता है। जबकि राष्ट्रवाद उद्देश्य पूरा होते ही सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। इस विषय को उन्होंने उदाहरण देकर भी समझाया। मोहन भागवत ने कहा, वैश्विक स्तर पर कहीं भी ईज्म (वाद) को ठीक से नहीं देखा जाता है। राजनीतिक विकास के क्रम में वाद को अपना लिया गया।

प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होने जाते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। जागरण

इससे पूर्व गुरुवार को आरएसएस की ओर से आयोजित संघ समागम में लोगों को संबोधित करते हुए डॉ. मोहन भागवत ने यूके की चर्चा करते हुए कहा था कि वहां नेशनलिज्म शब्द को गलत रूप में देखा जाता है। इस शब्द को नाजीवाद, फासीवाद, हिटलरिज्म आदि के रूप में देखा जाता है।

जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव सदाशिव गोलवलकर उर्फ गुरुजी, आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक रहे दीनदयाल उपाध्याय एवं दत्तोपंत ठेंगड़ी के साहित्य में भी राष्ट्रवाद शब्द कहीं नहीं दिखता है। संघ के प्रचारक और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री रहे हरेंद्र प्रताप पांडेय ने दैनिक जागरण के संपादकीय पृष्ठ पर छह अप्रैल 2019 को प्रकाशित लेख में भी इस बात का उल्लेख किया था। आरएसएस के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने भी पिछले वर्ष विश्व संवाद केंद्र के एक कार्यक्रम में कहा था कि राष्ट्रवाद शब्द सही नहीं है।

काश संघ-भाजपा गांधी के राष्ट्रवाद को समझते : कांग्रेस

कांग्रेस ने शुक्रवार को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर भाजपा और संघ परिवार पर हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि आज संघ परिवार और भाजपा ने खुद को राष्ट्रवाद से अलग कर लिया है। अब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब हिटलरशाही और फासीवाद है, लेकिन अगर आप महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद को समझते तो आपको राष्ट्रवाद से खुद को दूर करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि गांधी के राष्ट्रवाद की नींव प्यार है। गांधी का राष्ट्रवाद देश की सभी जातियों और धर्मों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है।

प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलने पर कोर्ट जाएगी भाजपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता: बंगाल में निकाय चुनाव से पहले घमासान शुरू हो गया है। भाजपा ने कहा है कि यदि चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है तो वह कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। मालूम हो कि बंगाल में अप्रैल के मध्य में निकाय चुनाव होना है। इसी बीच माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक की परीक्षा हो रही है। भाजपा की दलील है कि इस दौरान लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध होने के कारण चुनाव प्रचार के लिए उसे महज 10 से 15 दिन मिल रहे हैं।

चुनाव आयोग से उम्मीद : शुक्रवार को कोलकाता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि अगर चुनाव आयोग निकाय चुनाव में नियमों का पालन नहीं करेगा तो मजबूर होकर भाजपा को कोर्ट की ओर रुख करना पड़ेगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग ऐसा कुछ कदम नहीं उठाएगा जिसके चलते भाजपा को कोर्ट जाना पड़े। गुरुवार को भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर निकाय चुनाव की तिथि बढ़ाने की मांग की थी।

नगालैंड के उपमुख्यमंत्री पैटन के खिलाफ लोकायुक्त ने दिए जांच के आदेश

कोहिमा, प्रेट्र : नगालैंड के लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को उनके उपमुख्यमंत्री वाई. पैटन के खिलाफ प्रारंभिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। मामला 1,100 से ज्यादा कांस्टेबलों की भर्ती में नियम के विरुद्ध उपमुख्यमंत्री की संलिप्तता के आरोपों से जुड़ा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो को अगली सुनवाई से पहले हलफनामे के रूप में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि उपमुख्यमंत्री को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है।

नगालैंड के लोकायुक्त जस्टिस उमानाथ सिंह ने विका एस. अए की तरफ से की गई शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जांच आदेश पर गुरुवार को हस्ताक्षर किए। अए ने उपमुख्यमंत्री पैटन के खिलाफ बुधवार को शिकायत की थी। पैटन के पास ही गृह विभाग का भी जिम्मा है। अपने आदेश में लोकायुक्त ने समन्वयक अधिकारी अथवा नगालैंड लोकायुक्त पुलिस के निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज करने और प्रारंभिक जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं। यह जांच उच्चाधिकारी यानी मुख्यमंत्री करेंगे।

- मुख्यमंत्री करेंगे प्रारंभिक जांच, हलफनामा के रूप में सौंपनी होगी रिपोर्ट
- बिना विज्ञापन के पुलिस विभाग में 1135 पदों पर नियुक्तियां करने का है मामला

वाई. पैटन। फाइल

अए ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पैटन ने नगालैंड लोकसेवा आयोग (एनपीएससी) की लिखित परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के दौरान मदद के लिए संपर्क करने को कहा था। अए ने यह भी आरोप लगाया है कि पैटन ने बिना विज्ञापन के पुलिस विभाग में 1,135 पदों पर नियुक्तियां की थीं। उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में मंगलवार को सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत जानकारी के लिए आवेदन दिया जा चुका है। उपमुख्यमंत्री पैटन ने हाल ही में खत्म हुए विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि भर्ती की प्रक्रिया संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक और पुलिस बटालियन के कमांडेंट ने पूरी की।

उल्लेखनीय है कि नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के शासनकाल (2013-18) में पैटन राज्य के गृहमंत्री थे। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले पैटन एनपीएफ छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद भाजपा का नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (एनडीपीपी) के साथ गठबंधन हो गया। मार्च 2018 में पैटन राज्य के उपमुख्यमंत्री बने और उनके पास गृह समेत अन्य विभागों की जिम्मेदारी भी बनी रही।

शिकायतकर्ता की सुरक्षा के निर्देश : लोकायुक्त ने नगालैंड पुलिस के आयुक्त को शिकायतकर्ता की सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता व्हिसल ब्लोअर की श्रेणी में आता है और उसकी सुरक्षा में कोताही पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

योजना

पंजाब में आप के सामने है लीडरशिप का सबसे बड़ा संकट, विधायक परगट सिंह द्वारा सीएम को लिखे पत्र को इससे जोड़कर देखा जा रहा

सिद्धू के आप में जाने की तैयार हो रही जमीन

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- सिद्धू के नजदीकी परगट ने कैप्टन की कार्यशैली पर उठाए हैं सवाल
- कांग्रेस में इन दिनों नवजोत सिद्धू चल रहे हैं हाशिये पर

दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद पंजाब में एक बार फिर आम आदमी पार्टी को शिरोमणि अकाली दल-भाजपा गठजोड़ और कांग्रेस के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन दिक्कत है नेतृत्व (लीडरशिप) की। सबसे बड़ा सवाल है कि पार्टी को सत्ता तक ले कौन जाएगा? इसके लिए जो सबसे बड़ा नाम चल रहा है वह है नवजोत सिंह सिद्धू का।

सिद्धू इन दिनों कांगेस में हाशिये पर हैं। उनके करीबी कांग्रेस विधायक परगट सिंह ने जिस तरह से चार पेज का पत्र लिखकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं उससे इसके संकेत मिल रहे हैं कि सिद्धू किसी भी समय आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्हें आप में शामिल कौन करवाएगा? क्या आप उनकी ओर हाथ बढ़ाएगी या फिर सिद्धू खुद ऐसा करेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो उन्हें इस बात की संभावनाएं काफी कम लगती हैं कि सिद्धू आप में शामिल होंगे। विश्लेषकों को ऐसा भी नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी पंजाब में दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और अकाली दल के विकल्प के रूप में रूप में उभर सकती है। इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर डॉ. प्रमोद कुमार का मानना है कि अगर सिद्धू आप में शामिल हो भी जाते हैं तो इससे पंजाब का क्या भला होने वाला है? सिद्धू का आप में जाना समाचारों की सुर्खियां बन सकता है, लेकिन आप ने पिछले समय में न तो पंजाब में अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाई है और न ही पार्टी को संगठित करने का काम किया है। साफ सुथरी छवि वाले तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे में आप पारंपरिक पार्टियों की तरह ही देखी जाएगी।

मान व चीमा नहीं चाहेंगे कि सिद्धू पार्टी में शामिल हों : राजनीतिक विश्लेषक मालविंदर सिंह माली का मानना है कि सिद्धू के आप में जाने की अफवाहों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है। कांग्रेस में आने वाले दिनों में लीडरशिप में बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। सिद्धू इसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरा, उन्हें आप में आने कौन देगा? सांसद भगवंत मान और विपक्ष के नेता हरपाल चीमा ऐसा होने नहीं देंगे। मान पहले ही सभी अच्छे नेताओं को एक-एक करके बाहर कर चुके हैं। दूसरी बात दिल्ली और पंजाब की राजनीति में बहुत अंतर है। आप ने अपनी राजनीति की शुरूआत व्यवस्था बदलने से की थी, लेकिन अब वह मुफ्त शिक्षा, बिजली, पानी जैसे मुद्दे उभारकर सत्ता में लौटी है। यही नीतियां पारंपरिक पार्टियों की भी हैं।

नवजोत सिंह सिद्धू। फाइल

सीएम से कम पर सिद्धू नहीं मानेंगे

पंजाब की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले अमरिंदर सिंह के मुताबिक, नवजोत सिंह सिद्धू किसी कीमत पर आप में नहीं जाएंगे। सिद्धू के आप में शामिल होने के सवाल पर भगवंत मान के जवाब को सुनकर तो कोई नहीं कह सकता कि वह उन्हें पार्टी में आने देंगे। सीएम की कुर्सी के भरोसे से कम पर बात नहीं बनेगी। सिद्धू को यह भरोसा देगा कौन? भगवंत मान या अरविंद केजरीवाल? अगर केजरीवाल देंगे तो मान का क्या होगा? इससे पहले सुच्चा सिंह छोटेपुर, सुखपाल सिंह खैहरा, गुरप्रीत घुग्गी सरीखे नेताओं का भगवंत मान ने क्या हाल किया है, सभी को पता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी गलती सिद्धू करेंगे। ज्ञात हो, छोटेपुर, खैहरा, घुग्गी आदि पहले आप में थे, लेकिन अब नहीं हैं।

कोलकाता में शाह की सभा के लिए अनुमति नहीं दे रही पुलिस

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

एक बार फिर कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री और दिग्गज भाजपा नेता अमित शाह की सभा के लिए कोलकाता पुलिस अनुमति देने नहीं दे रही है। सेना की ओर से कोलकाता के धर्मतल्ला स्थित शहीद मीनार मैदान में सभा की अनुमति दे दी गई है। बावजूद इसके कोलकाता पुलिस रोड़े अटका रही है। पुलिस का तर्क है कि उस समय राज्य में उच्च माध्यमिक परीक्षा है। ऐसे में लाउडस्पीकर बजाकर सभा का प्रचार करने से परीक्षार्थियों के लिए परेशानी खड़ी होगी। सेना ने अनुमति दे दी है। पुलिस हर दफा सत्तारूढ़ तृणमूल नेताओं के इशारे पर भाजपा नेताओं की सभा व रैली में बाधा उत्पन्न करती है। अब इस मुद्दे पर भी सियासत गरम होने के पूरे आसार हैं।

सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन और धरना के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आगामी एक मार्च को कोलकाता में सभा होनी है। इस सभा में शाह नागरिकता संशोधन कानून लागू करने के लिए उनका अभिनंदन किया जाएगा।

सेना ने गुरुवार को ही शहीद मीनार मैदान में सभा के लिए हरी झंडी दे दी है। परंतु, कोलकाता पुलिस की ओर से अब तक अनुमति नहीं मिली है। शुक्रवार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ कोलकाता पुलिस के अधिकारियों की बैठक हुई। जिसके बाद पुलिस ने साफ कहा कि शहीद मीनार मैदान में उस समय किसी भी सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशानुसार परीक्षा के समय राज्य के किसी भी अंचल में लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि कोर्ट का भी यही आदेश है। हालांकि प्रदेश भाजपा ने शाह की सभा रद करने या फिर स्थगित करने की भी घोषणा नहीं की है।